

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी./1-ए-वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: 760 / न.नि. / इलेक्ट्रिक वाहन / 2023-24

दिनांक 03/08/2023

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

विषय: उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के विभिन्न प्रस्तारों में विहित प्राविधानों के कार्यान्वयन एवं कृत कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के पत्र संख्या 2667/77-6-23-6099-161/2023 दिनांक 02 अगस्त 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के विभिन्न प्रस्तारों में विहित प्राविधानों के कार्यान्वयन एवं कृत कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में लोक भवन, सी-ब्लाक स्थित उनके सभाकक्ष में दिनांक 08.08.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे बैठक आहूत किये जाने की सूचना प्रेषित करते हुये दिनांक 04 अगस्त 2023 तक एजेण्डा बिन्दु की अद्यतन स्थिति/आख्या इन्वेस्ट यू.पी. को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2 उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न एजेण्डा के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं पर आख्या अपेक्षित है:-

Sr. No.	Agenda	Information Required	Status on Action Taken	Way Forward
1	Adoption of Guidelines for setting up Public Charging Stations	1) Status of such adoption of the Model-bye laws for setting up EV charging infrastructure in UP. Copy of the GO issued for such adoption.	A new chapter "Provision of Electric Vehicle Charging Infrastructure" has been included in proposed amendment in building bye-laws. This proposal is under consideration at the government level.	-
2	Identification of Land Bank for Charging	1) Status of identification of Land bank by each Deptt. 2) Details of identified Land parcels by each Deptt. 3) Empanelment of agencies for location viability analysis to set up charging stations	-	-
3	Provide Govt Land on revenue sharing model	1) Number of MoUs signed / or status of any tender (EOI) floated	-	-
4	Data of Existing Charging Stations	<ul style="list-style-type: none">Number of existing charging stations and their locations,Number of charging stations being established with locations,Number of charging stations to be established in view of future requirements and strategy	-	-

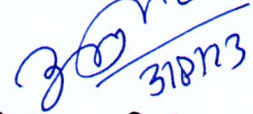
		for their speedy establishment		
5	Funds sanctioned under any Gol/ State scheme to promote EV ecosystem	<ul style="list-style-type: none"> • If any funds are being sanctioned under any Gol/ State scheme for promoting EV mobility. Share details of such scheme, aid provided so far (year-wise) and its utilisation status (with issues if any). • Any other assistance provided by Gol/ State for promoting EV mobility with status • Any other related initiatives taken up other than Gol schemes with status 	-	-

3 अलग कराना है कि उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 2 से 5 के सम्बन्ध अंकित सूचनायें आपके अभिकरण से सम्बन्धित है। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में पत्र के साथ संलग्न लिंक के माध्यम से सूचनायें दिनांक 04 अगस्त 2023 को मध्याह्न 12:00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचनायें प्रेषित किये जाने का लिंक निम्नवत् है:-

<https://forms.gle/JPpbN7mWw1msLWnw5>

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र शासन।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी. पिकप भवन, लखनऊ।
3. उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।



(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

I/361194/2023

बैठक: दिनांक 08/08/2023मध्याह्न 12:00 बजेसंख्या-2667/77-6-23-6099-161/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/आवास एवं शहरी नियोजन/खाद्य एवं रसद/नगर विकास/परिवहन विभाग, 30प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, 30प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ।
3. निदेशक, नगरीय परिवहन/यूपीनेडा/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, 30प्र0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लखनऊ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडा/यीडा/सीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6लखनऊ : दिनांक 02/08/2023

विषय- 30प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के विभिन्न प्रस्तरों में विहित प्राविधानों के कार्यान्वयन एवं कृत कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 30प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के विभिन्न प्रस्तरों में विहित प्राविधानों के कार्यान्वयन एवं कृत कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में लोक भवन, सी-ब्लाक स्थित उनके सभाकक्ष में दिनांक 08/08/2023 को मध्याह्न 12:00 बजे बैठक आहूत की गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार निर्धारित बैठक में सुसंगत सूचनाओं एवं विवरण के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

बैठक के सम्बन्ध में एजेन्डा संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया दिनांक 04/08/2023 को अपराह्न 05 बजे तक अपने विभाग से सम्बन्धित एजेन्डा बिन्दु की अद्यतन स्थिति/आख्या इन्वेस्ट यूपी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इन्वेस्ट यूपी बैठक से पूर्व पी0पी0टी0 तैयार कर शासन को प्रस्तुत कर सके।

मुख्यावास के बाहर स्थित कार्यालय के अधिकारीगण आभासी (वर्चुअल) रूप से प्रतिभाग करेंगे। बैठक का लिंक निम्नवत है-

Meeting ID: 838 7583 2057

Passcode: EV@321

संलग्नक : यथोक्त।

Signed by मनोज कुमार
मौर्य

भवदीय,

Date: 02-08-2023 16:31:56 (मनोज कुमार मौर्य)

Reason: Approved

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)

उप सचिव।

Enclosure

Agenda

Point-1: Adoption of 'Guidelines for setting up Public Charging Stations'

- ✓ This is regarding the 'Model guidelines' prepared by Chief Town & Country Planner, Uttar Pradesh vide CTCP Letter No. 193/ N.Ne.(2)/Electric Vehicle/ 2020-21 dated 11.06.2020 by adapting to various guidelines issued by MoHUA and MoP for setting up Public Charging Infrastructure.
- ✓ These have been shared by IIDD to Housing & Urban Planning Deptt for adoption at various Development Authorities and to NOIDA / GNIDA/ YEIDA/ UPSIDA/ SIDA/ GIDA/ DMIC-IITGNL as well for further adoption vide. IID6 Letter No.25/ 2020/2058/77-6-20-LC.02/18 TC-3 dated 04.08.2020.

Related Deptt:

- 1) Housing & Urban Planning Deptt
- 2) NOIDA, GNIDA, YEIDA, UPSIDA, SIDA, GIDA, UPEIDA

Information required: Status of such adoption of the Model-bye laws for setting up EV charging infrastructure in UP. Copy of the GO issued for such adoption.

Point-2: Establishment of a 'Working Group on Fast track development of Charging Infrastructure' under chairmanship of Urban Development Deptt

(Section 3.1(10): **Role-** "To ensure smooth implementation of the model bye-laws and regulate the strategy as well as implementation of development of charging / swapping facilities in the State".
Members: "Representatives from Housing Deptt, Energy Deptt (DISCOMs), Chief Town & Country Planner (CTCP), Transport Deptt, Industry Deptt and other relevant Govt Agencies & Local Bodies.")

Related Deptt: Urban Development Deptt

Information required:

- Status of such Working Group; if established, then copy of notification through which such Working Group has been set up.
- Number of meetings held and the key decisions taken at these meetings of the Working Group.

Point-3: Identification of Land Bank for Charging

(Section 3.1(2): "The State Government shall promote creation of charging / swapping facilities in public parking spaces, Metro stations, Bus depots/ Terminals, petrol pumps, Govt Buildings, Corporate Buildings, Educational/ Health Institutes, Shopping-malls & other commercial places, Group Housing societies and RWAs, Gram Sabha land, etc. The State Urban Development Department, Transport Department, Housing Department and Panchayati Raj Department shall facilitate in the identification of such locations and development of charging/ swapping facilities";

Section 3.1(4): "The Urban Local Bodies shall take up parking policy reforms in cities for developing public charging / swapping facilities in parking spaces, In the short term, local authorities may identify spaces for reservation in public parking for EV charging";

Section 3.1(5): "The State Government is coordinating with NITI Aayog and Asian Development Bank (ADB) in formulating a 'Comprehensive Electric Mobility Plan (CEMP)' for Lucknow. This initiative shall be extended to all 17 Cities with Municipal Corporations, which may further be extended to other cities in the later phases with the help of Niti Aayog or any other institution..... Through these plans, Urban Local Bodies/ Other Govt Agencies will be able to identify locations and land parcels for creation of charging infrastructure."

Related Deptt:

- 1) Urban Development Deptt - Land Bank in Municipal areas including 17-Cities with Municipal Corporations, at City Transport Stations, Smart Cities/ Amrut Cities
- 2) Housing Deptt - Land Bank at Development Authorities
- 3) Energy Deptt/ UPPCL - Land Bank at DISCOMs
- 4) Transport Deptt/ UPSRTC - Land Bank at UPSRTC Bus stations
- 5) UP Metro Rail Corporations- Land Bank at Metro Stations
- 6) UPEIDA, NOIDA, GNIDA, YEIDA, UPSIDA, GIDA- Land Bank in IDA areas
- 7) Food & Civil Supplies Deptt - Land Bank at Petrol Pumps
- 8) Panchayati Raj Deptt - Land Bank in Gram Samaj areas

Information required:

- Status of identification of Land bank by each Deptt.
- Details of identified Land parcels by each Deptt.
- Empanelment of agencies for location viability analysis to set up charging stations

Point-4: Provide Govt Land on revenue sharing model

(Section 3.1(3): "State Government shall facilitate land to service providers for setting up Charging facilities in the State" - on lease for 10years at revenue sharing model @Re 1 per kWh - by signing prescribed MoU as per MoP Guidelines dated 14.01.2022 with PSUs; and through tender with Private players.)

Related Deptt: As per above (Deptt with available Land Bank)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) Urban Development Deptt | 6) NOIDA, GNIDA, YEIDA, UPSIDA, |
| 2) Housing Deptt | GIDA |
| 3) Energy Deptt/ UPPCL | 7) Food & Civil Supplies Deptt |
| 4) Transport Deptt/ UPSRTC | 8) Panchayati Raj Deptt |
| 5) UP Metro Rail Corporations | |

Information required: Number of MoUs signed / or status of any tender (EOI) floated

Point-5: Formulating Comprehensive EV Mobility plans

(Section 3.1(5): "The State Government is coordinating with NITI Aayog and Asian Development Bank (ADB) in formulating a 'Comprehensive Electric Mobility Plan (CEMP)' for Lucknow. This initiative shall be extended to all 17 Cities with Municipal Corporations, which may further be extended to other cities in the later phases with the help of Niti Aayog or any other institution.")

Related Deptt: Urban Development Deptt

Information required: Besides CEMP-Lucknow which was released on 14.06.2023, if Deptt has taken up development of plans for any other city. If yes, which agency is involved and what is the status of such plan.

Point-6: Identifying Green routes/ Strategic routes for EV Mobility

(Section 4.1.(1): "The State Government is coordinating with NITI Aayog and Asian Development Bank (ADB) in formulating a 'Comprehensive Electric Mobility Plan (CEMP)' for Lucknow. This initiative shall be extended to all 17 Cities with Municipal Corporations, which may further be extended to other cities in the later phases with the help of Niti Aayog or any other institution.....
Section 4.1.(1-b): "Identify green routes in these cities & suitable peri urban areas for promoting EV"; Section 4.2: Green routes shall be identified in each district (other than 17 Cities with Municipal Corporations) by 2025 and ensure E-buses on each of these select routes.")

Related Deptt:

- 1) Urban Development Deptt (Urban Transport)
- 2) Transport Deptt

Information required:

- Status of identification of such routes and their details
- Whether any fleet operator is empanelled on the select routes identified. If yes, what is type and number of EV-vehicles running and their status.
- Future plan for engaging EV players for public transportation on the select routes

Point-7: Promote EV Adoption

- ✓ Retro-fitment - Section 4.1.(5): "The State Government shall promote retro-fitted EVs in the State with certified technology (ARAI/ ICAI or any other). Towards this, separate guidelines and its implementation shall be issued and managed by State Transport Department";
- ✓ Aggregators
- ✓ Scrapping Policy

Related Deptt: Transport Deptt

Information required:

- Status of guidelines issued to promote retro-fitment technology for all EV-segments
- Status of strategy developed to promote Fleet aggregators (viz. Ola, Rapido, Swiggy, etc.) to adopt EV

- Status of GoI Scrapping Policy adopted with details of ICE vehicles scrapped segment wise and year-wise

Point-8: Facilitate Power for setting up Charging infrastructure

(Section 3.1. (7): DISCOMs shall ensure fast-track electricity connections to EV Battery charging/ swapping service providers and implement the EV tariff established by SERCs. DISCOMS shall also ensure that EV battery charging / swapping facilities are connected and are operating properly, preventing improper use of EV connections, managing the distribution network, and undertaking grid upgrades based on growth in load including from EV charging. In this context, the guidelines issued by GoI/ Niti Ayog from time to time shall be followed."

Related Deptt: Energy Deptt (DISCOMs)

Information required:

- Details of DISCOM-wise power-connection provided to any charging station anywhere in the state in last 5-years (Year-wise data)
- Details of currently active procedure for providing power connection to any Charging Station(s) in the State
- Status of guidelines issued to provide power connection and related support to public charging stations

Point-9: Facilitate Power for setting up Charging infrastructure

(Section 3.1.(6): "The State Government shall regularly coordinate with UPERC for rationalising the tariff rate from time to time for EV charging in the State.;"
Section 3.1.(8): State Government shall allow 'Open Access' at charging/ swapping station or swapping kiosk, having contract cumulative demand of 1MW & above"

Related Deptt: Energy Deptt (DISCOMs)

Information required:

- Status of ERC's current guidelines on EV tariff and if these may be rationalised further
- Details of DISCOM-wise Open-access provided to any charging station anywhere in the state in last 2-years (Year-wise data)

Point-10: Data of Existing Charging Stations

Related Deptts:

- 1) Energy Deptt
- 2) Urban Development
- 3) Housing Deptt
- 4) Transport Deptt
- 5) UPEIDA/ NOIDA/G.NOIDA/ UPSIDA/ YEIDA

Information required:

- Number of existing charging stations and their locations,
- Number of charging stations being established with locations,
- Number of charging stations to be established in view of future requirements and strategy for their speedy establishment.

Point-11: Funds sanctioned under any GoI scheme to promote EV ecosystem

Related Deptts:

- 1) Energy Deptt (UPPCL- DISCOMs)
- 2) Urban Development
- 3) Housing Deptt
- 4) Transport Deptt
- 5) Environment & Climate Change Deptt (UPPCB)
- 6) Addl Sources of Energy Deptt (UPNEDA)
- 7) UPEIDA/ NOIDA/G.NOIDA/ UPSIDA/ YEIDA

Information required:

- If any funds are being sanctioned under any GoI scheme/ policy for promoting EV mobility. Share details of such scheme, aid provided so far (year-wise) and its utilisation status (with issues if any).
- Any other assistance provided by GoI for promoting EV mobility with status
- Any other related initiatives taken up other than GoI schemes with status

.....

Note: For more details of Policy, please visit: <https://invest.up.gov.in/uttar-pradesh-electric-vehicle-manufacturing-policy-2022/>